सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टें [1962]

नव रतनमल और अन्य

प्रति

स्टेट ऑफ राजस्थान

(न्यायमूर्तिगण पी.बी. गजेंद्रगढ़कर, ए.के. सरकार, के.एन. वांछो0, के.सी. दास गुप्ता और एन. राजगोपाल अयंगर)

भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 149 (1908 का IX) की संवैधानिकता सरकार द्वारा मुकदमों के लिए साठ वर्ष- भारत का संविधान, अनु. 14.

सरकार ने एक सरकारी कोषाध्यक्ष और बांड के निष्पादन में शामिल होने वाले कुछ जमानतदारों द्वारा निष्पादित सुरक्षा बांड के आधार पर मुकदमा दायर किया। रक्षा में विवाद, अन्य बातों के अलावा, वह अनुच्छेद थी। भारतीय सीमा अधिनियम की धारा 149 में सरकार द्वारा मुकदमों के लिए 60 साल की सीमा का प्रावधान करती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में असंवैधानिक था। जो इस अधिनियम के अनुच्छेद 83 के तहत वर्जित था। माना जाता है कि परिसीमा के क़ानून लाभकारी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे किसी व्यक्ति को वह चीज़ छीनने से रोका जा सके जिसे उसे लंबे समय से अपना मानने की अनुमति दी गई है और जिसके विश्वास पर वह अपने भविष्य के जीवन की योजना बनाता है। यदि मुकदमा किसी निजी व्यक्ति द्वारा होता तो मुकदमा अनुच्छेद 83 के अंतर्गत आता। और इसके द्वारा वर्जित किया गया होता, लेकिन राज्य के मामले में अलग-अलग विचार सामने आते हैं और सरकार और निजी व्यक्तियों के दावों के बीच अंतर होता है। सीमा अधिनियम, 1908 का अनुच्छेद 149, जो सरकार द्वारा मुकदमों के लिए 60 साल की अवधि तय करता है, सरकार और निजी व्यक्तियों के बीच वर्गीकरण का एक उचित आधार है, और सरकार को मुकदमा दायर करने के लिए सटीक अवधि की अनुमति दी जानी चाहिए। विधायी नीति का मामला हो और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

पुरूषोत्तम गोविंदजी हलाई वि. देसाई, [1955] 2 एस.सी.आर. 887. मालाबार के कलेक्टर वि. इब्राहिम, [1957] एस.सी.आर. 970 एवं मन्नालाल वि. झालवार के कलेक्टर, [1961] 2 एस.सी.आर. 962, आवेदन किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1957 की सिविल अपील संख्या 454। निर्णय और आदेश दिनांक दिसंबर से अपील। 16, 1954, न्यायिक आयुक्त न्यायालय, अजमेर में सिविल अपील संख्या 134 सन 1952 में।

अपीलकर्ताओं की ओर से एवी विश्वनाथ शास्त्री, एसएन एंडली, रामेश्वर नाथ और पीएल वोहरा।
जी. सी. कासलीवाल, महाधिवक्ता, राजस्थान, एस. के.
प्रतिवादी की ओर से कपूर और टी. एम. सेन।
24 अप्रैल 1961 को न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

न्यायमूर्ति अयंगर, -यह न्यायिक आयुक्त, अजमेर द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र पर एक अपील है, और यह आर का राज्य है, जो 16 दिसंबर, 1954 के उस न्यायालय के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा प्रतिवादी संघ के पक्ष में डिक्री दी गई थी। भारत की पुष्टि की गई।

सेठ लाल चंद कोठारी-हमारे समक्ष अपील में मूल प्रथम अपीलकर्ता (इस अपील के लंबित रहने तक उनकी मृत्यु हो गई और उनके उत्तराधिकारियों को उनके कानूनी प्रतिनिधियों-अपीलकर्ता 1 से 6 के रूप में रिकॉर्ड पर लाया गया है) को आयुक्त अजमेर-मेरवाड़ा सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। कोषाध्यक्ष, अजमेर-मेरवाड़ा, ने 20 फरवरी, 1940 के एक आदेश द्वारा, उनके प्रभार के तहत दो कोषागार अजमेर में और एक उप-कोषागार ब्यावर में होगा। पद ग्रहण करने से पहले, नियमों के तहत, उन्हें रुपये की सीमा तक सरकारी प्रोमिसरी नोट जमा करने थे। 60,000 और इन कोषागारों में सरकार को होने वाले किसी भी नुकसान को कवर करने के लिए दो जमानतदारों के साथ इतनी ही राशि का एक सुरक्षा बांड भी निष्पादित करें। तदनुसार उन्होंने जमा राशि जमा कर दी, और 27 फरवरी, 1940 को सेठ फूलचंद के साथ एक सुरक्षा बांड निष्पादित किया गया - जो अब अपील में 7वें अपीलकर्ता हैं और एक सेठ कंवरलाल रांका जिनकी मुकदमे से पहले ही मृत्यु हो गई थी और उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया था। इस में। इसके बाद लाल चंद कोठारी को कोषाध्यक्ष के रूप में कार्यालय का कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया और उन्होंने 6 मार्च, 1940 को ऐसा किया। हमारा संबंध अजमेर के खजाने से नहीं, केवल ब्यावर के खजाने से है। कार्यभार संभालने के समय लाल चंद ने "चार्ज-रिपोर्ट" शीर्षक से एक रसीद तैयार की थी और इसमें लिखा है कि उन्होंने पिछले पदाधिकारी (एम.एल. पटनी) से नकदी की वह रकम ले ली थी जो उनके खाते में होनी चाहिए थी। पुस्तकों के अनुसार राजकोष. 1940 और 1948 के बीच कुछ नहीं हुआ और राजकोष में कामकाज नियमित रूप से और नियमों के अनुसार चलता हुआ दिखाई दिया। यह उल्लेख किया जा सकता है कि सामान्य रूप से समय-समय पर जांच और ऑडिट होते थे। सरकारी अधिकारी द्वारा लेकिन इन जाँचों या ऑडिट के दौरान कोई अनौचित्य नहीं पाया गया। 31 मार्च, 1948 को अजमेर के अतिरिक्त सहायक आयुक्त रल्लनमल ने ब्यावर के राजकोष का हजस्थान चेक बनाया। राजकोष के जिन कर्मचारियों को वहां होना चाहिए था, वे अय्यंगार जे में अनुपस्थित थे,

बावजूद इसके कि उन्हें उनके आगमन की पूर्व सूचना मिल गई थी और इसके बाद उन्होंने राजकोष को सील करने का निर्देश दिया। इस उप-कोषागार में दो नकदी तिजोरियाँ थीं - एक एकल ताले से सुरक्षित थी, जिसकी चाबी कोषाध्यक्ष के कर्मचारियों के पास थी और दूसरी दोहरे ताले वाली थी, जिसकी चाबियाँ कर्मचारी के पास होती थीं। एक कोषाध्यक्ष का और दूसरा सरकारी खजाना अधिकारी-तहसीलदार का। दोनों चेस्टों में शेष राशि के सत्यापन से पता चला कि सिंगल-लॉक चेस्ट से 7 आने, 9 पाई और रुपये गायब थे। डबल-लॉक के साथ चेस्ट से 84,215 रु. इसके बाद सरकार ने रुपये की सुरक्षा से गायब राशि की वसूली के लिए कार्यवाही की। 60,000 जो जमा के अधीन थे। सरकारी प्रतिभूतियाँ बेची गईं और उन्हें लगभग 58 हजार रुपये प्राप्त हुए और लगभग रु. 25,786-13-9 अभी भी बकाया है। इसके बाद भारत संघ ने इस राशि की वसूली के लिए लाल चंद कोठारी और सेठ फूल चंद के खिलाफ 27 फरवरी, 1940 को सुरक्षा बांड पर उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, ब्यावर के समक्ष 1951 का सिविल सूट 125 दायर किया। प्रतिवादियों द्वारा कई बचाव पेश किए गए लेकिन उन सभी को विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने खारिज कर दिया, जिन्होंने उत्तरदाताओं को मुकदमे में प्रार्थना की गई शर्तों के अनुसार डिक्री प्रदान की। प्रतिवादियों ने न्यायिक आयुक्त के पास अपील दायर की, जिन्होंने इसे खारिज कर दिया, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछ बचाव पक्ष ने 27 फरवरी, 1940 के सुरक्षा बांड की व्याख्या को चालू कर दिया, अनुच्छेद के तहत एक प्रमाण पत्र दिया गया। संविधान की धारा 133(1) और इस प्रकार अपील अब अमेरिका के समक्ष है। न तो गबन से होने वाले नुकसान का तथ्य और न ही इसकी राशि प्रश्न में है, और केवल विचार के लिए उठाए गए बिंदु हैं। (1) क्या बांड की शर्तों पर अपीलकर्ताओं के पक्ष में डिक्री बरकरार रखी जा सकती है; (2) क्या मुकदमे में दावा परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं था। इस पर दूसरा तर्क यह था कि यदि भारतीय सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 83 ने इस दावे को नियंत्रित किया कि इसे वर्जित किया जाएगा, और यह प्रावधान अनुच्छेद में निहित है। 149 सरकार द्वारा मुकदमों के लिए 60 साल की सीमा अवधि निर्धारित करना अनुच्छेद के उल्लंघन के रूप में असंवैधानिक था। संविधान के 14. यह आखिरी याचिका है जिसके कारण अय्यंगार जे की अपील इस बड़ी पीठ द्वारा सुनी जा रही है।

पहले बिंदु के संबंध में कि मुक़दमे का दावा सुरक्षा बांड की शर्तों के भीतर नहीं समझा गया था, विद्वान वकील ने तीन प्रस्तुतियाँ दीं: (1) प्रतिवादियों को उत्तरदायी बनाने के लिए, सरकार द्वारा किए गए नुकसान को साबित करना होगा 6 मार्च, 1940 को या उसके बाद हुआ, जिस दिन अकेले लाल चंद कोठारी ने राजकोष का कार्यभार संभाला था। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि यद्यपि वाद में निर्धारित सीमा तक हानि ब्यावर के राजकोष में हुई थी, वादी-प्रतिवादी ने यह साबित नहीं किया था कि यह 6 मार्च 1940 के बाद हुई थी। दूसरे शब्दों में, तर्क यह था कि 6 मार्च, 1940 को जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो कोई भौतिक जांच नहीं की गई और इस वजह से कोई निश्चित नहीं हो सका कि

क्या यह एक नुकसान था जो कार्यालय में पिछले पदधारी की अवधि के दौरान हुआ था या निश्चित रूप से मार्च के बाद की अवधि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था। 6, 1940. इस तर्क को नीचे की अदालतों ने खारिज कर दिया और, हमारी राय में, यह सही है। लाल चंद कोठारी द्वारा निष्पादित रसीद के सामने यह दावा करना उनके लिए खुला नहीं होगा कि इसमें लिखावट सही नहीं थी, और किसी भी स्थिति में यह उन्हें दिखाना होगा कि यह गलत था और निश्चित रूप से , उसके इसे स्थापित करने की कोई संभावना नहीं थी।

(2) इसके बाद यह आग्रह किया गया कि आसपास की परिस्थितियों के संदर्भ में पढ़ी गई बांड की शर्तों के अनुसार लाल चंद कोठारी केवल कमी के लिए उत्तरदायी होंगे। सिंगल-लॉक वाले चेस्ट में स्थान और डबल-लॉक वाले दूसरे चेस्ट में हानि या गबन या कमी के लिए नहीं। इस तर्क का पूरा आधार यह था कि रुपये की सुरक्षा जमा राशि। 60,000 और कोषाध्यक्ष द्वारा निष्पादित इतनी ही राशि का सुरक्षा बांड इस बात का संकेत था कि यह उस राशि के संदर्भ में था जो सिंगल-लॉक के तहत छाती में अधिकतम थी और इस सुविधा से यह था कि प्रस्तुतीकरण बिना किसी आधार के है, क्योंकि अपील में आग्रह किया गया कि पार्टियों का इरादा यह था कि लाल रतनमत चंद कोठारी दूसरे चेस्ट में किसी भी गबन, हानि या कमी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। बांड के तहत यह दायित्व इसकी शर्तों अयंगार पर निर्भर करेगा और दस्तावेज़ में इस्तेमाल की गई भाषा के सामने वकील को एहसास हुआ कि प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। गंभीरता से बनाए रखा जाए।

(3) इस शीर्ष के अंतर्गत अंतिम निवेदन यह था कि डबल-लॉक वाली तिजोरी में जो नुकसान हुआ, वह सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता था और इसलिए कोषाध्यक्ष की देनदारी को बाहर रखा गया था। विद्वान वकील ने इस तथ्य पर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया कि बांड की शर्तों ने लाल चंद को सरकारी अधिकारियों द्वारा गबन के लिए भी उत्तरदायी बना दिया, भले ही उनका उन पर कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन अगर लाल चंद उन शर्तों से सहमत हैं - और इस पर कोई विवाद नहीं है, तो शर्तें पहले से होनी चाहिए। घूंघट. हालाँकि, सुरक्षा बांड की शर्तों के अलावा, यह स्पष्ट होगा कि यदि किसी ताले की चाबी कोषाध्यक्ष के कर्मचारी के पास थी तो उसके बिना गबन नहीं हो सकता था। कर्मचारी की मिलीभगत या लापरवाही. यदि ऐसा है, तो नियोक्ता पर दायित्व तय करना बांड की शर्तों से उत्पन्न होने वाली देनदारी के अलावा अनुचित भी नहीं हो सकता है, और उसके नौकरों की लापरवाही या कदाचार के लिए इस तरह की परोक्ष देनदारी कम नहीं होती है। सरकारी अधिकारियों की सहायता या लापरवाही का कारण। ये बांड की शर्तों के आधार पर आग्रह किए गए बिंदुओं को समाप्त करते हैं। यह केवल इस विवाद से निपटना बाकी है कि दावा अनुच्छेद के तहत सीमा द्वारा वर्जित है। परिसीमा अधिनियम की धारा 83 उस दलील पर कि परिसीमा अधिनियम की धारा 149 जो सरकार द्वारा मुकदमों के लिए 60 वर्ष की अवधि तय करती है, अनुच्छेद का उल्लंघन करते हुए असंवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 14 में यह आग्रह किया जाता है कि सरकार के दावों को उस समय के मामले में निजी

व्यक्तियों के दावों से अलग मानने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है जिसके भीतर उन्हें मुकदमे द्वारा लागू किया जा सकता है।

विद्वान वकील ने आग्रह किया कि साहित्य के क़ानून विश्राम के क़ानून हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किए गए हैं। दावों को उत्तेजित नहीं किया गया, ताकि उचित समय के बाद लोग इस आधार पर आगे बढ़ सकें कि उन्हें उनके खिलाफ संभावित दावों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। इन सिद्धांतों पर खुद को आधारित करते हुए, विद्वान वकील का तर्क यह था कि आंदोलनकारी दावों के प्रयोजन के लिए सरकार और निजी व्यक्तियों के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है और कोई भी तर्कसंगत आधार पर कोई कानून इसकी अनुमति नहीं दे सकता है। राज्य द्वारा दावों के लिए लंबी अवधि की सीमा कायम रखी जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लॉर्ड केन्योन ने जो वर्णन किया है वह सच है परिसीमा के क़ानून "आराम के क़ानून" के रूप में (प्रति देखें)। टॉल्सन बनाम काये (')) में डलास, सी.जे. और ब्रैमवेल, बी हालाँकि, "शांति के क़ानून" (हंटर बनाम गिबन्स (")). कभी-कभी विपरीत राय भी व्यक्त की गई है। में रे बेकर (), कॉटन, एल.जे. ने लिमी की दलीलों का अवलोकन किया, राष्ट्र को कभी भी हेय दृष्टि से नहीं देखा जाएगा चूंकि इनका उपयोग स्पष्ट रूप से देय ऋणों को चुकाने के लिए किया जाता है। यह है हालाँकि सिद्धांत की आगे जाँच करना अनावश्यक है सीमा के अंतर्निहित क़ानून. हम आगे बढ़ेंगे आम तौर पर स्वीकृत आधार पर कि वे डिज़ाइन हैं एक लाभकारी सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अर्थात् किसी के पास जो कुछ है उसे छीनने से रोकें लंबे समय से अपने और पर विचार करने की अनुमति दी गई है। जिस विश्वास के आधार पर वह अपने जीवन, आदतों और खर्चों की योजना बनाता है। हालाँकि, यह राज्य के दावों और उन्हें लागू करने के लिए सीमा पट्टी के प्रावधान के मामले में व्यक्ति के दावों के बीच अंतर करने के तर्कसंगत आधार के विरुद्ध नहीं है। इस मामले पर विचार करते समय दो बिंदुओं को अलग रखा जाना चाहिए: (1) क्या निजी व्यक्तियों द्वारा दावों को लागू करने के लिए उपलब्ध समय में किसी भी भिन्नता के प्रावधान के बीच एक अंतर निकाला जा सकता है या एक वर्गीकरण का समर्थन किया जा सकता है। राज्य, (2) क्या, यदि ऐसा वर्गीकरण अच्छा होता, तो अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई 60 वर्ष की अवधि। भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 149 इतनी लंबी अवधि है जो अनुचित है। हम इन दोनों बिंदुओं के बीच अंतर की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं क्योंकि विद्वान वकील ने कहा है यह कहना सही है कि इसमें कोई तर्क नहीं है। इस तथ्य पर अधिक बल दिया गया है कि अनुच्छेद 149 द्वारा नव रतनमल की परिसीमा की अवधि 60 वर्ष निश्चित की गई है। और यह समय की एक अनुचित रूप से लंबी अवधि थी। यदि विद्वान वकील निजी व्यक्तियों और सरकार को कार्रवाई के लिए सीमा प्रदान करने का आधार प्रदान करता है तो वह सफल हो सकता है; लेकिन अगर वह वहां गलत है और सही दृष्टिकोण यह है कि वर्गीकरण का तर्कसंगत आधार है, तो सरकार को मुकदमा दायर करने के लिए जो अवधि दी जानी चाहिए वह विधायी नीति

का मामला होगा और इसे दायरे में नहीं लाया जा सकता है या अनुच्छेद 14 के तहत एक चुनौती का दायरा या वास्तव में संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद का। इसलिए यह पर्याप्त है यदि हम स्वयं को पहले बिंदु तक ही सीमित रखें, अर्थात, क्या सरकार के साथ मतभेद का कोई तर्कसंगत आधार है। उस अवधि के संबंध में किराया जिसके भीतर सरकार के बीच दावों को रखा जा सकता है।

एक ओर और निजी व्यक्ति दूसरी ओर। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि परिसीमन अधिनियम, हालांकि विश्राम का एक क़ानून है और शीर्षकों को शांत करने के लिए है, और इस अर्थ में प्रतिवादी के दृष्टिकोण से समस्या को देखता है ताकि उसे सुरक्षा प्रदान की जा सके। बासी दावों के विरुद्ध, साथ ही वादी की स्थिति को भी संबोधित करता है। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, जहां वादी नाबालिग होने या पागल होने या मूर्ख होने के कारण मुकदमा दायर करने की तार्किक अक्षमता के तहत है, यह उस विअनुच्धेदंगता को ध्यान में रखते हुए अवधि के विस्तार के लिए प्रावधान करता है। इसी प्रकार, किसी दावे की सुरक्षा में सार्वजनिक हित को एस द्वारा ध्यान में रखा जाता है। अधिनियम के 10 में यह प्रावधान किया गया है कि एक्सप्रेस ट्रस्ट के मामले में कोई सीमा अवधि नहीं होगी। इन प्रावधानों के विवरण में जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन यह बताना पर्याप्त है कि यहां का दृष्टिकोण दावों की प्रवर्तनीयता की रक्षा के दृष्टिकोण से है, जो कि यदि सामान्य नियम लागू होते हैं, तो सीमा से वर्जित हो जाएंगे। इस सिद्धांत पर काफी हद तक यह कहा जाता है कि यह वैधानिक प्रावधान के अधीन है, जबकि अधिकतम विजिलेंटिबस एट नॉन डॉर्मिएंटिबस जुरा सबवेनियंट विषय के लिए एक नियम है, अधिकतम नलम टेम्पस घटित होता है। यह सामान्यतः क्राउन पर लागू होता है। कोक के हवाले से बताया गया कारण यह था कि राज्य को अपने अधिकारियों की लापरवाही या विरोधी पक्ष के साथ उनकी कपटपूर्ण मिलीभगत के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में अनुच्छेद में निहित विशेष प्रावधान का प्रश्न उठता है। अधिनियम की धारा 149 को देखना होगा। सबसे पहले, हमारे पास यह तथ्य है कि सरकार के मामले में, यदि कोई दावा सीमा से बाधित हो जाता है, तो नुकसान जनता पर पड़ता है, यानी, सामान्य रूप से समुदाय पर और निजी व्यक्ति के लाभ पर पड़ता है जो चूक से लाभ प्राप्त करता है। समय की। यह अपने आप में किसी व्यक्ति के दावों और बड़े पैमाने पर समुदाय के दावों के बीच अंतर करने के लिए पर्याप्त आधार का संकेत देता प्रतीत होता है। आगे, यह उल्लेख किया जा सकता है कि सरकारी तंत्र के मामले में, यह एक ज्ञात तथ्य है कि यह व्यक्तियों के मामले में उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ता है। उचित अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित करने में होने वाली देरी के अलावा कि कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है - सरकार एक अवैयक्तिक निकाय है, दावा शुरू करने से पहले नियमों के अनुसार अंतर-विभागीय पत्राचार, परामर्श, मंजूरी प्राप्त करनी होती है। इनमें आवश्यक रूप से समय लगता है और यह उन विशेषताओं के कारण है जिन्हें कभी-कभी लालफीताशाही के रूप में जाना जाता है, जिससे सरकारी कार्यालयों के कामकाज में देरी होती

है। यह ठीक इसी कारण से है कि हमारे पास शुरुआती सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान हैं जो 1908 की संहिता में जगह पाते हैं, जैसे 0.27, आरआर। 5 और 7 पढ़ना: "ओ. 27. आर. 5. सरकार को वादी का जवाब देने के लिए दिन तय करते समय न्यायालय, उचित माध्यम से सरकार के साथ आवश्यक संचार के लिए और सरकार को निर्देश जारी करने के लिए उचित समय देगा वकील को सरकार की ओर से उपस्थित होकर जवाब देना होगा और वह अपने विवेक से समय बढ़ा सकता है। 0. 27. आर. 7 (1). जहां प्रतिवादी एक सार्वजनिक अधिकारी है और सम्मन प्राप्त करते समय, वादपत्र का उत्तर देने से पहले सरकार को संदर्भ देना उचित समझता है, तो वह न्यायालय में आवेदन कर सकता है। सम्मन में निर्धारित समय का इतना विस्तार प्रदान करें जो उसे ऐसा संदर्भ देने और उचित चैनल के माध्यम से उस पर आदेश प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो।
(2) ऐसे आवेदन पर न्यायालय तब तक समय बढ़ाएगा जब तक यह आवश्यक प्रतीत हो।" इन सबके अलावा, विशेषांक में अंतर्निहित अनुपात भी मायने रखता है! "राजस्व वसूली अधिनियम" और "सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम" जैसे निजी व्यक्तियों के बकाया को लागू करने के लिए उपलब्ध नहीं होने वाली प्रक्रिया द्वारा मुकदमे का सहारा लिए बिना सरकार को देय राशि की सारांश वसूली के प्रावधान, जो कानून की किताब में हैं एक सदी से भी अधिक समय भी समान है, अर्थात्, जनता और समुदाय की रुचि यह समझने में कि इसके कारण क्या है, शीघ्रता से; और ऐसे प्रावधानों की संवैधानिक वैधता इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई है। पुरषोत्तम गोविंदजी हलाई बनाम देसाई (¹) में इस न्यायालय ने माना कि एस. बॉम्बे भूमि राजस्व अधिनियम, 1876 की धारा 13, जिसके आधार पर धारा के तहत प्रमाणित मांग की वसूली के लिए जारी वारंट के अनुसरण में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 46(2) ने अनुच्छेद का अपमान नहीं किया। संविधान के 14. इसी तरह, मालाबार के कलेक्टर बनाम इब्राहीम (2) में धारा के तहत आयकर मांग के संबंध में एक डिफॉल्टर की गिरफ्तारी। मद्रास राजस्व वसूली अधिनियम की धारा 48 को अनुच्छेद का अपमान न करने वाला माना गया। संविधान के 14. शायद इस न्यायालय का अधिक तात्कालिक प्रासंगिकता वाला एक और निर्णय, जिसमें अब यह मुद्दा उठाया गया है कि सरकार के दावों और निजी व्यक्तियों के दावों के बीच अंतर करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है - पर विचार किया गया और उसे अस्वीकार कर दिया गया, वह है मन्नालाल बनाम कलेक्टर, जाहलवार (') जिसमें 7 दिसंबर, 1960 को फैसला सुनाया गया था। इस आखिरी मामले में इस न्यायालय के समक्ष यह आग्रह किया गया था कि सरकार को देय राशि की वसूली का सारांश तरीका जिसके लिए राजस्थान सार्वजनिक वसूली द्वारा प्रावधान किया गया था। वहां अधिनियम को आक्षेपित किया गया - वसूली का तरीका जो निजी नागरिक के लिए उपलब्ध नहीं था - के समान संरक्षण का उल्लंघन किया गया 2 एस.सी.आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत कानून का उल्लंघन किया गया और यह विवाद निरस्त कर दिया गया। इसलिए

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के तर्क को सिद्धांत के आधार पर और साथ ही इस न्यायालय के निर्णयों के अनुपात के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए।

अपील विफल हो जाती है और जुर्माने के साथ खारिज कर दी जाती है।

Vetted by-Mohan Kumar, ADJ Mohammadi, Kheri